of another firm engaged in manufacture and supply of the same item, Chief Adviser (Cost) recommended wage escalation, worked out on the basis of actual date rather than adoping 0.1 per cent as done earlier. Both the methods of arriving at wage escalation are provided in the contract agreement. After examining the entire issue the Ministry of Railways decided that the wage escalation factor should be based on verification of actual data by the Chief Adviser (Cost).

बगहा और छितौनी के बीच पुल का पुनर्निर्माण कार्य

4299. **श्री ईश दत्त यादव** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बगहा और छितौनी के बीच पुल के पुनर्निर्माण कार्य पर आने वाली लागत की हिस्सेदारी का क्या प्रावधान है;

(ख) किस राज्य ने अपनी हिस्सेदारी नहीं दी है ; और

(ग) उक्त कार्य का कितना प्रतिशत कार्य सम्पन्न हो चुका है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के०सी० लेंका) : (क) बगहा और छितौनी के बीच रेल-एवं-सड़क पुल की लागत में जल संसाधन मंत्रालय, रेल मंत्रालय और बिहार तथा उत्तर प्रदेश सरकारों की हिस्सेदारी इस प्रकार रहेगी :

1. भूमि की लागत सहित गाइड बांधों और उनकी सुरक्षा जैसे पानी के बहाव को नियंत्रित करने संबंधी कार्यों की लागत जल संसाधन मंत्रालय, उत्तर प्रदेश और बिहार सरकारों द्वारा 5:3:2 के अनुपात में वहन की जाएगी ।

2. भूमि की लागत सहित रेल-एवं-सड़क पुल के लिए सामान्य उप-संरचना की लागत रेल मंत्रालय, उत्तर प्रदेश और बिहार सरकारों द्वारा 2:1:1 के अनुपात में वहन की जायेगी ।

3. रेल पुल अधिरचना और रेलपथ की समूची लागत रेलवे द्वारा वहन की जाएगी ।

4. सडक पुल अधिरचना की लागत में उत्तर प्रदेश और बिहार सरकार का बराबर का हिस्सा रहेगा ।

5. भूमि की लागत सहित खादर में दो पहुंच तटबंधों की लागत में रेल मंत्रालय और उत्तर प्रदेश तथा बिहार सरकार का हिस्सा 70% 15% 15% के अनुपात में रहेगा पिचिंग और टर्फिंग की लागत में रेलों और उ० प्र० तथा बिहार की राज्य सरकारों की हिस्सेदारी 2:1:1 के अनुपात में रहेगी ।

6. खादर के भीतर सड़क का खड़ंजा बिछाने की लागत में दोनों राज्यों सरकारों का हिस्सा बराबर रहेगा, सेतु बंधन और ग्रेड प्रथक्करण, यदि कोई हो, सहित खादर के बाहर की सडक की लागत, संबंधित राज्य सरकारों द्वारा वहन की जाएगी ।

(ख) किसी भी अन्य सहभागीदार, यथा, जल संसाधन मंत्रालय और उत्तर प्रदेश तथा बिहार सरकारों ने अभी तक अपने हिस्से की समूची राशि का भुगतान नहीं किया है ।

(ग) दिसम्बर, 1992 तक 39% ।

Revenue earnings by Railways

4300. SHRI SUKOMAL SEN:
SHRI SUNIL BASU RAY:

Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Railways have exhausted all avenues of revenue earnings and is poised for substantial fare hikes; and

(b) if so, which section is going to be provided with added comforts more — the upper class or the second class passengers?